प्रेषक.

अर्जुन सिंह अपर सचिव उत्तराखण्ड शासन

सेवा में.

अपर प्रमुख वन संरक्षक नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन उत्तराखण्ड, देहरादून.

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2

Section-2 Austra/Sanction 10-11/Plan/Plan 10-11.do

विषय:-अनुदान सं0-27 के आयोजनागत पक्ष की केन्द्र पुरोनियानित योजना-''पार्कों एवं पक्षी विहारों का विकास'' के अन्तर्गत वर्ष 2010-11 की वित्तीय स्वीकृति.

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-नि0-718/3-6(पार्क पक्षी) दिनांक 29 नवम्बर, 2010, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के "बिन्सर वन्य जीव विहार" हेतु निर्गत पत्र सं0-13 00 02 24/WL दिनांक 16 सितम्बर, 2010, "गोविन्द वन्य जीव विहार" हेतु निर्गत पत्र सं0-21 00 06 24/WL दिनांक 16 सितम्बर, 2010 तथा "फूर्नों की घाटी राष्ट्रीय पार्क" हेतु निर्गत पत्र सं0-13 00 30 24/WL दिनांक 25 अक्टूबर, 2010, के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वन विभाग के अन्तर्गत संचालित योजना-पार्कों एवं पक्षी विहारों का विकास(100 प्रतिशत के०स०) योजना हेतु पूर्व में अवमुक्त धनराशि के अतिरिक्त संलग्न तालिका में अंकित विवरणानुसार चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 में ₹ 97,41,000/-(₹ स्तानवे लाख इक्तालीस हजार मात्र)की धनराशि निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) धानराशि का आहरण / व्यय वास्तविक आवश्यकतानुसार किश्तों में किया जाय तथा धनराशि उन्हीं कार्यों में तथा उन्हीं शर्तों एवं प्रतिबन्धें के अनुसार व्यय की जाय जिस हेतु केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति की गई हो.
- (2) उक्त धनराशि वर्णित योजना हेतु समक्ष स्तर से अनुमोदित कार्ययोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यो/मदों पर ही व्यय किया जाय और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग अन्य कार्यों के क्रियान्वयन के लिए त किया जाय.
- (3) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू योजनाओं पर एवं उन्हीं मदो/कार्यों हेंतु किया जायेगा, जिसका अनुमोदन भारत सरकार द्वारा योजनान्तर्गत किया गया हो। किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नये/भिन्न कार्यों के कार्यान्वयन के लिए न किया जाय तथा विभिन्न मदों में व्यय से पूर्व वित्त अनुमाग–1 के शासनादेश स0–187/XXVII(1)/2010, दिनांक 30 मार्च, 2010 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार एवं यथास्थिति सक्षम स्तर की अनुमति शासन का अनुमोदन प्राप्त कर ही किया जाय. शासन द्वारा वांछित सूचनायें एवं विवरण निर्धारण प्रारुप व समयबद्ध आधार पर शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1(वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1(लेखा नियम), आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2008, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सनिश्चित किया जाय।
- (4) यह संज्ञान में आया है कि धनराशि विभागाध्यक्षों के निवर्तन पर रखने के उपरान्त भी विभागाध्यक्षों द्वारा वह धनराशि आहरण वितरण अधिकारियों के निवर्तन पर नहीं रखी जाती है, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर व्यय हेतु धनराशि उपलब्ध नहीं होती है. अतः आपके निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि आहरण वितरण अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय, जिससे की फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो, परन्तु यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि धनराशि का आहरण वास्तविक मांग आधार पर किश्नतों में किया जाय.
- (5) आहरण वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशि का विवरण बीळ्म०-17 पर प्रत्येक माह प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा.
- (6) अनुदान के अन्तर्गत होने वाली सम्भावित व्यय की फेजिंग (त्रैमास के आधार पर) प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा, जिससे की राज्य स्तर पर कैश-फ्लो निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो.
- (7) बीएएम0-13 पर नियमित रूप से प्रशासकीय विभाग एवं वित्त विभाग को विलम्बतम 20 तारिख तक पूर्ण माह की सूचना उपलब्ध कराई जाय.
- (8) व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है. अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के समबन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय. इस सम्बन्ध में वेतन आदि मदों के अतिरिक्त शेष मदों में मितव्ययिता सुनिश्चित करने के लिए तत्काल शीर्षक/मद्वार ब्युत की कार्ययोजना बना ली जाय तथा तद्नुसार विशेषकर आ योजनेत्तर पक्ष में बचत करने का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित कर बचत किया जाना सुनिश्चित किया जाय.
- (9) मानक मदों के आहरण प्रणाली के सम्बन्ध में शासनादेश सं0-ब-06/X-2-2010-12(11)/2009 दिनांक 31 मार्च, 2010 द्वारा दिये गर्थ दिशा-निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी.
- (10) जो निर्माण कार्य आरम्भ किये जा चुके हैं, के परिप्रेक्ष्य में स्वीकृत कार्य, आगणन की धनराशि, निर्गत वित्तीय स्वीकृति इत्यादि का विवरण वित्त विभाग के शासनादेश-485/XXVII(1)/2009, दिनांक 16 जुलाई, 2009 द्वारा निर्धारित किये गये प्रक्रियानुसार निर्धारित प्रपत्नों पर प्रशासकीय विभाग, नियोजन विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय.

क्रमशः.....2

- (11) योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुसार ही किया जाये तथा जहां आवश्यकता हो सक्षम अधिकारी/शासन की पूर्व सहमति/स्वीकृति ली जाय.
- (12) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार एवं शासन के वित्त विभाग को वर्षान्त तक अवश्य उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चि किया जाय.
- (13) अप्रयुक्त धनराशि बजट मैनुअल के प्रावधानों के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा.
- (14) निर्माण कार्यों के लागत व समय वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कड़ी कार्यवाही व संघन अनुश्रवण किया जायेगा एवं इस हेतु बजट मैनुअल के प्रस्तर-211(डी) की अनुपालन स्निश्चित की जायेगी.
- (15) विभागाध्यक्ष द्वारा वर्ष के प्रारम्भ में तथा हर माह की 10 तारीख तक वित्त एवं नियोजन विभाग को केन्द्र सहायतित/बाह्य सहायतित योजनाओं में अनुमोदित परिव्यय के सापेक्ष केन्द्रांश की धनराशि तथा केन्द्र सरकार से प्राप्त हुई धनराशि का विवरण उपलब्ध कराएंगे. उक्त सूचना के अभाव में वित्तीय अधिकारों पर रोक लगा दी जायेगी. केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाले अवशेष धनराशि का विवरण भी प्रतिमाह उपलब्ध कराया जायेगा.
- (16) यह वित्तीय स्वीकृति इस शर्त/प्रतिबन्ध के अधीन भी है कि चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 में अगली वित्तीय स्वीकृति तभी निर्गत की जायेगी, जबकि निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं प्रत्येक योजना के सम्बन्ध में स्टेटस रिपोर्ट अर्थात योजना कब प्रारम्भ की गई, कितने वर्षों के लिए योजना है, योजना का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य कितना है तथा लिखत योजना के सापेक्ष कितना भौतिक लक्ष्य अभी प्राप्त हो चुका है एवं कितना शेष है, आदि के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा तथा यह भी कि गत वित्तीय वर्ष 2009-10 में निर्गत की गई समस्त वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा.
- (17) उपरोक्त वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के अधीन भी है कि पूर्व में निर्गत वित्तीय स्वीकृतियों का प्रगति विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दी जायेगी.
- 2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के अनुदान सं0-27 के लेखाशीर्षक 2406-वानिकी तथा वन्य जीवन 02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीवन 110-वन्य जीवन परिरक्षण 01-केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें 0109--''पार्कों एवं पक्षी विहारों का विकास'' योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित तालिका में अंकित विवरणानुसार सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगाः-

(धनराशि रें हजार में)

वित्तीय वर्ष 2010–11 में वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित भारत सरकार का पत्र/दिनांक	भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कुल अनुमोदित घनराशि (₹ लाख में)	, मानक मद	<b>बजट</b> प्रावधान	पू <b>र्व</b> में निर्गत धनराशि	वर्तमान वित्तीय स्वीकृति
1		2	3		4
13000224/WL	22.63	15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की ख.	1400	200	300
Dt. 16.9.2010	•	18- प्रकाशन	1000	200	25
(बिन्सर वन्य जीव विहार)		२०-सहायक अनुदान/अंश दान/राज सहायता	1500	0	231
		24-वृहत निर्माण कार्य	6000	400	1350
21000624/WL	52.18	25-लघु निर्माण कार्य	14000	90	975
Dt. 16.9.2010 (गोविन्द वन्य जीव विहार)		26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	3000	50	545
		29-अनुरक्षण	11000	560	4424
12002004/7577		42-अन्य व्यय	2500	190	1521
13003024/WL Dt. 25.10.2010 (फूलो की घाटी राष्ट्रीय पार्क)	22.60	44~प्रशिक्षण व्यय	1500 +	** *5 480	370
योग र्वमान स्वीकृति ₹ स्वतन्त्रे स्वयः	97.41		41900	2570	9741

(वर्तमान स्वीकृति ₹ सतानवे लाख इक्तालीस हजार मात्र)

3. ये आदेश वित्त विभाग के अ०शा०सं०-372(P)/XXVII(4)/2010, दिनांक 27 जनवरी, 2011 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं. संलग्नक-यथोपरि.

भवदीय

(अर्जुन सिंह) अपर सचिव

क्रमशः.....3

## संख्या-367 (1)/x-2-2011, तद्दिनांकित.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1. महालेखाकार(लेखा एवं लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून.
- 2. महालेखाकार(आर्डिट), उत्तराखण्ड, वैभव पैलस, सी-1/105, इन्दिरानगर, देहरादून.
- 3. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून.
- 4. प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव)/मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड शिविर कार्यालय-देहरादून.
- 5. मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन तथा लेखा परीक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून.
- 6. मुख्य वन संरक्षक, सर्तकता एवं कानून प्रकोच, उत्तराखण्ड, देहरादून.
- 7. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.
- 8. वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.
- 9. आयुक्त, कुमाऊ/गढ़वाल मण्डल.
- 10. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड.
- 11. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून.
- 12. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड.
- 13. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय, देहराद्न.
- 14 प्रभारी, एन.आई.सी., उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून.
- 15. गार्ड फाइल.

आझा से, िहिन्न (अहमद अली) अनु सचिव

## शासनादेश सं0- 367 /x-2-2010-12(63)2010, दिनांक 0 जनवरी, 2011 का संलग्नक:-

क्र. सं.	मानक मद	बिन्सर वन्य जीव विहार	गोविन्द वन्य जीव विहार	फूलों की घाटी	योग
				gader <b>≪</b> da	A Company of the Comp
1	15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	100	100	100	300
2	18- प्रकाशन	0	25	0	. 25
3	20-सहायक अनुदान/अंश दान/राज सहायता	31	200	Q	231
4	24-वृहत निर्माण कार्य	950	0	400	1350
5	25-लघु निर्माण कार्य	300	575	100	975
6	26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	0	45	500	545
7	29-अनुरक्षण	732	2952	740	4424
8	42-अन्य व्यय	150	1141	230	1521
9	44-प्रशिक्षण व्यय	o	180	190	370
	योग	2263	5218	2260	9741

(वर्तमान स्वीकृति ₹ सतानवे लाख इक्तालीस हजार मात्र)